

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *35 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 03 फरवरी, 2023/14 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है

फेरी सेवा का विकास

+*35. श्री सुनील कुमार मंडल :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का भारत में फेरी सेवाओं के और विकास के लिए गंगा विलास की तर्ज पर विभिन्न स्थानों पर अन्य कूज शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे अनुमानतः कितना लाभ अर्जित होने की संभावना है;
- (ख) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिसके तहत भारत में विदेशी कूज की तुलना में यात्री संरक्षा एवं सुरक्षा सहित यात्री कूज शिप उन्नयन कार्य और सेवा से संबंधित काम बेहतर और आधुनिक तरीके से किया जा सके;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा भविष्य में क्या पहल की जाएगी; और
- (घ) हाल ही में आरंभ किए गए गंगा विलास कूज तथा इसकी संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों तथा उस पर किए गए व्यय सहित कूज सेवाओं हेतु बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

''फेरी सेवा का विकास'' के संबंध में श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा पूछे गए दिनांक 03 फरवरी, 2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *35 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक में संदर्भित विवरण

(क) : पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मुंबई में 14-15 मई, 2022 को पहली अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय कूज कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें विश्व के अग्रणी कूज प्रचालकों ने भाग लिया था। जलमार्गों में डुबाव और नौचालन सहायताएं सुनिश्चित करने तथा निर्मित और नियोजित जेट्टियों के बारे में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया कार्य साझा किया गया था। उन्होंने भारत में नदी कूज पर्यटन की क्षमता का दोहन करने में रुचि दिखाई थी। मैसर्स हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड ('मैसर्स अंतरा रिवर कूज' के ब्रांड नाम के अंतर्गत प्रचालित), मैसर्स एडवेंचर रिसोर्ट एंड कूज प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स जे. एम. बक्शी एंड कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित किए गए थे। जलमार्गों पर किया गया जमीनी कार्य-

i. दिनांक 13.01.2023 को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर वाराणसी से डिब्रूगढ़, असम तक सबसे लंबे रिवर कूज का प्रारंभ हुआ।

ii. गंगा, ब्रह्मपुत्र, केरल के बैकवाटर्स, ओडिशा आदि में विभिन्न नदी कूजों में बुकिंग्स में बढ़ोतरी हुई है।

सरकार द्वारा की गई पहलों और नदी कूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लाभों का ब्योरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) और (ग) : भारत में नदी कूज पर्यटन के विकास के लिए कार्य योजना सहित ''रिवर कूज विजन 2047'' की तैयारी के लिए आईडब्ल्यूआई द्वारा एक अध्ययन चलाया गया है। आईडब्ल्यूआई राष्ट्रीय जलमार्गों में नौचालन योग्य जलमार्ग और जेट्टियां उपलब्ध करा रहा है, जिन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ कूज जलयान और सेवाएं उपलब्ध कराते हुए कूज प्रचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, और जो भारतीय तथा पूरे विश्व से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य सरकारें, इन पर्यटकों को अपनी सर्वोत्तम सांस्कृतिक, हस्तशिल्प, पर्यटन और आतिथ्य उत्पाद प्रदान करते हुए पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं।

(घ) : माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2023 को गंगा विलास के द्वारा सबसे लंबी नदी कूज यात्रा को हरी झंडी (ऑनलाइन) दिखाई गई थी, जो रा.ज.-1 पर वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से चलकर 01 मार्च, 2023 को ब्रह्मपुत्र नदी (रा.ज.-2) पर डिब्रूगढ़ (असम) पहुंचेगी। भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर रा.ज.-1 और 2 के बीच यह यात्रा लगभग 3,200 कि.मी. की जलमार्ग दूरी तय करेगी।

आईडब्ल्यूआई अधिनियम, 1985 के अनुसार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) नौवहन एवं नौचालन हेतु राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) के विकास और विनियमन के लिए उत्तरदायी है। कार्गो जलयानों के लिए टर्मिनलों सहित विकसित की गई अवसंरचना का प्रयोग नदी कूजों द्वारा भी किया जाता है। आईडब्ल्यूआई नदी कूज पर्यटन के लिए एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है। आईडब्ल्यूआई द्वारा सुरक्षित नौचालन के लिए जलयान को पायलेटेज और एस्कोर्ट प्रदान किया जाता है।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- i. नौचालन चैनल का अनुरक्षण; बैंडलिंग और ड्रेजिंग कार्य करना
- ii. नौचालन सहायताएं जैसे बत्तियों सहित बॉयज, रात्रि नौचालन (उच्च घनत्व के जलखंड), मस्तूल आदि
- iii. चैनल का जलीय सर्वेक्षण तथा मार्करों के साथ डिजिटल मैप में अद्यतन सूचना
- iv. आपात स्थिति के मामले में टग्स और बचाव जलयान
- v. आप्रवासन ब्यूरो और सीमा-शुल्क विभाग के साथ समन्वय
- vi. नौचालन सहायता हेतु बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण (बीआईडब्ल्यूटीए) के साथ समन्वय
- vii. हितधारकों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों पर मुख्य जानकारी हासिल कर सकने हेतु परिसंपत्ति एवं नौचालन सूचना पोर्टल (पीएएनआई)
- viii. जलयानों की बर्थिंग के लिए टर्मिनल अवसंरचना; विद्युत आपूर्ति, बंकर ऑयल
- ix. पोटून पुल खोलने, एचटी लाइनों के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय

नदी कूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लाभ

- i. नदी कूज, पश्चिमी के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, आधुनिक सुविधाओं और अवसंरचना विकसित करने के बाद भारत के पर्यटन राजस्व में बढ़ोतरी करते हैं।
- ii. इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभ मिलने के साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजित होंगे और वे लाभान्वित होंगे।
- iii. स्थानीय नौका प्रचालकों, होटल मालिकों और रेस्तरां संचालकों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को हैंडल करने का प्रशिक्षण देकर कुशल/गैर-कुशल रोजगार उपलब्ध होंगे।
- iv. यह कुछ हद तक स्थानीय बाजारों जैसे कि हस्तशिल्प को भी लाभ प्रदान करेगा।
- v. इस प्रकार, यह रोजगार उपलब्ध कराकर जलमार्गों की पश्चिमी में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने में मदद करेगा।
- vi. यह पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार करेगा।
